मध्य प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता

3506. **श्री अजीत जोगी :**
श्री पृथ्वी माझी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य के कुछ जिलों में बढ़ती हुई नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय या अन्य सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या दृष्टिकोण अपनाया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस समस्या को हल करने के लिए कोई नई पहल करने का विचार रखती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुख्यत: यह राज्य सरकार ईसे संबंधित विषय है। तथापि, जब भी कोई आवश्यकता होगी, केन्द्र सरकार राज्य सरकार को सभी सम्भव सहायता देगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

3507. **श्री अजीत जोगी**
श्री पृथ्वी माझी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त आयोग और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधनों को कब तक अंतिम रूप दे दिये जाने की संभावना है ; और

(ख) फौजदारी संबंधी मामलों के निपटान में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को दूर करने के लिये और क्या नई पहल और कार्यवाही की जा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) विधि आयोग और राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशें, पर सरकार द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1988 को सरकार ने 13-5-1988 को लोक सभा में प्रस्तुत किया था जो कि अभी तक उस सदन में लंबित है। अधिनियम की धारा 22, 28, 30, 31, 33 और 36 में प्रस्तावित संशोधन से फौजदारी मामलों का निपटान शीघ्रता से होगा।

Financial assistance to farmers under Insurance Scheme and Credit Guarantee Scheme

3508. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any financial help is given to the farmers under the Deposit Insurance Scheme and Credit Guarantee Scheme; and

(b) if so, what are the details thereof for the last three years, Statewise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) The present data reporting system does not generate the information in the manner asked for. However, deposits insured by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) and the